

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
20.08.2025 के
तारांकित प्रश्न सं. 396 का उत्तर

बागेश्वर जिले के लिए रेल संपर्क

*396. श्री अजय भट्ट:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने बागेश्वर जिले को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए किसी रेल परियोजना की योजना बनाई है;
- (ख) यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति, अनुमानित लागत और समय-सीमा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में इस संबंध में कोई कार्य योजना बनाने का विचार है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 20.08.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 396 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): टनकपुर-बागेश्वर नई लाइन (170 कि.मी.) के लिए फील्ड सर्वेक्षण पूरा हो गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की लागत 48,692 करोड़ रु. आंकी गई है। इस परियोजना में यातायात संभावनाएं कम हैं।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद, परियोजना की स्वीकृति के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि से आवश्यक अनुमोदन अपेक्षित होते हैं। चूंकि परियोजनाएं स्वीकृत करना सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की जा सकती है।

उत्तराखण्ड:

हाल के वर्षों में बजट आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। उत्तराखण्ड राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों हेतु बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	187 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2025-26	4,641 करोड़ रु. (लगभग 25 गुना)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, उत्तराखण्ड राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 40,384 करोड़ रु. की लागत वाली कुल 216 किलोमीटर लंबाई की 03 नई लाइनें स्वीकृत की गई हैं। इसका सार निम्नानुसार है:-

कोटि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	कुल लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च 2025 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	03	216	16	19,898

उत्तराखण्ड राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली मुख्य परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:

- हाल ही में, देवबंद-रुड़की नई लाइन परियोजना (27 कि.मी.) पूरी कर ली गई है। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी लगभग 40 कि.मी. कम हो जाएगी।
- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई रेल लाइन परियोजना (125 कि.मी.) भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो पूरी तरह से उत्तराखण्ड राज्य में आती है। यह हिमालय के दुर्गम भूवैज्ञानिक और चुनौतीपूर्ण भूभाग से होकर गुजरती है। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड में संपर्कता में बदलाव लाना है। यह परियोजना उत्तराखण्ड के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों से होकर गुजरती है और देवप्रयाग तथा कर्णप्रयाग जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों को ऋषिकेश और भारत की राष्ट्रीय राजधानी तक रेल संपर्कता मुहैया कराएगी।

इस परियोजना में 105 कि.मी. लंबी 16 मुख्य लाइन सुरंगों, लगभग 98 कि.मी. लंबी 12 बचाव सुरंगों का निर्माण कार्य शामिल है। अभी तक, 13 मुख्य लाइन सुरंगों और 9 बचाव सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। सभी 8 प्रवेश मार्गों का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। कुल 213 किलोमीटर की सुरंग निर्माण परियोजना में से 199 किलोमीटर सुरंग निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य पारस्परिक प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकतानुसार शुरू किए जाते हैं। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/ आधुनिकीकरण के लिए कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन के समय निचली श्रेणी के स्टेशनों की तुलना में उच्च श्रेणी के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

उत्तराखण्ड राज्य में स्टेशन विकास परियोजनाएं:

भारतीय रेल ने ग्राहकों के यात्रा अनुभव में संवर्द्धन तथा बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए, दीर्घकालिक इष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में स्टेशनों के सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणबद्ध रूप से इन्हें क्रियान्वित करना शामिल है। इस मास्टर योजना में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार।
- शहर के दोनों ओर के साथ स्टेशन का एकीकरण।
- स्टेशन भवन में सुधार।
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था और वाटर बूथ में सुधार।
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉनकोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैंप का प्रावधान।
- प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार/प्रावधान और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कवर
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान।
- पार्किंग क्षेत्र, मल्टीमॉडल एकीकरण।
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ।
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली।
- प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एकजीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि का प्रावधान।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता और व्यवहार्यता के अनुसार संवहनीय और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेलपथ आदि का प्रावधान तथा दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर का निर्माण भी शामिल है।

इस योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 11 स्टेशनों की विकास कार्यों हेतु पहचान की गई है। उत्तराखण्ड राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास हेतु पहचाने गए स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

राज्य	अमृत स्टेशनों की सं.	अमृत स्टेशनों के नाम
उत्तराखण्ड	11	देहरादून, हरिद्वार जं., हर्रावाला, काशीपुर जं., काठगोदाम, किंच्छा, कोटद्वार, लाल कुआं जं., रामनगर, रुड़की, टनकपुर

उत्तराखण्ड राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास संबंधी कार्य अच्छी गति से शुरू किए गए हैं और इनमें से कुछ स्टेशनों पर कार्य की प्रगति निम्नानुसार है:

- काठगोदाम स्टेशन पर प्रतीक्षालय, शौचालय ब्लॉक और प्रवेश लॉबी के सुधार संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं। लिफ्ट, परिचलन क्षेत्र, पहुँच मार्ग और दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं के सुधार संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- काशीपुर जंक्शन स्टेशन पर आधुनिक शौचालय ब्लॉक, परिचलन क्षेत्र का सुधार, पार्किंग, प्रांगण का निर्माण, प्लेटफार्म की सतह को ऊंचा करना और उसकी सतह में सुधार लाने के कार्य पूरे हो गए हैं। स्टेशन भवन, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं और लिफ्ट के सुधार संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- लाल कुआं जंक्शन स्टेशन पर प्लेटफार्म की सतह को ऊंचा करने और उसकी सतह में सुधार लाने, परिचलन क्षेत्र और पार्किंग का सुधार, वाटर बूथ, संकेतकों, प्रकाश व्यवस्था, स्टेशन भवन के सुधार संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं। 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज और दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- रामनगर स्टेशन पर शौचालय ब्लॉक, पुराने स्टेशन भवन का सुधार, प्रतीक्षालय, प्रांगण का निर्माण, प्लेटफार्म की सतह को ऊंचा करना, यात्री आरक्षण प्रणाली भवन का विस्तार, परिचलन क्षेत्र का विकास, नए प्लेटफार्म शेल्टर, साइनेज, प्रकाश व्यवस्था, भू-दश्यांकन और दिव्यांगजन सुविधाओं के लिए स्पर्शनीय पथ, वाटर बूथ, कम ऊँचाई वाले टिकट काउंटर, पार्किंग और रैम्प का कार्य पूरा हो चुका है। फिनिशिंग के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- टनकपुर स्टेशन पर स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, शौचालय, प्लेटफार्म शेल्टर के सुधार संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं। प्लेटफार्म शेड, लिफ्ट, साइनेज, प्रकाश व्यवस्था और दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

उत्तराखण्ड राज्य में आरओबी/आरयूबी

रेल परिचालन में संरक्षा और सड़क उपयोगकर्ताओं की गतिशीलता में सुधार लाने के लिए, समपार आदि के स्थान पर उपरि सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों (आरओबी/आरयूबी) का निर्माण किया जाता है। 2014-25 के दौरान, उत्तराखण्ड राज्य में 106 आरओबी/आरयूबी का निर्माण किया गया है।

इसके अलावा, 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, उत्तराखण्ड राज्य में 158 करोड़ रु. की लागत पर 9 आरओबी/आरयूबी स्वीकृत किए गए हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।
